

प्रेषक.

एम०एच० खान, सचिव उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समाज कल्याण अनुमाग-3

देहरादून दिनांक ८२ र लाह 2012

विषय:-बहुक्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार में हैण्डपम्प की स्थापना से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक, भारत सरकार के शासनादेश संख्या-3/20(2)/2008-PP-1 दिनांक 28 फरवरी, 2011 तथा पैयजल अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या:-415 दिनांक 18 अप्रैल 2012 (छायाप्रतियाँ संलग्न) के क्रम में बहुक्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार में निम्नलिखित परियोजना के अंतर्गत ₹ 8.84 लाख की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नानुसार अधोवर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन इतनी ही धनराशि आहरण करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करत हैं-

क्रमांक	जनपद	परियोजना का नाम/कुल लागत	भारत सरकार द्वारा संस्तुत कुल आवंटन (केन्द्रांश 76%)	भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत कुल धनरशि।	पेयजल विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 18.4.2012 द्वारा स्वीकृत राज्यांश	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा स्त्रीकृत की जा रही धनराशि
1,	हरिद्वार	हैण्ड पम्पां की स्थापना / 8.84	6.63	3.32	2.21	6.63

उक्त धनराशि के अंतर्गत ₹ 6.63 लाख की धनराशि प्रस्तर-15 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अंतर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष एवं ₹ 2.21 लाख की धनराशि, जो कि पेयजल विभाग के शासनादेश दिनाक 18 अप्रैल, 2012 के द्वारा जिलाधिकारी, के निर्वतन पर रखी गयी है, के सापेक्ष वहन की जायेगी।

उक्त धनराशि इस आशय से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि वर्तमान 3. योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुयी धनराशि ₹3.32 लाख (कुल अपेक्षित केन्द्रांश ₹ 6.63 लाख के सापेक्ष) का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित अवशेष केन्द्रांश की प्राप्ति भी सनिश्चित कर ली जाएगी।

भारत सरकार के शासनादेश संख्या-3/20(1)/2008-PP-1 दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 में 4.

निहित प्रतिबन्ध / दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-515/XXVII(1)/2008 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में 5. उल्लिखित समरत शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। 6.

अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवाय रूप 7. से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशपलो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत
शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति

प्राप्त करके ही किया जाए।

9. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंविटत धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकिस्मक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्ये बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या—15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

10. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11. यदि किसी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग अपेक्षित हो तो उसका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों केंअंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार

समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत उक्त स्वीकृत हैण्डपप्प लगने के एक माह के भीतर भौतिक सत्यापन आख्या शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

बी०एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करें।

12.

14.

15. इस संबंध में होने वाला व्यंय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—15 के लेखाशीर्षक 2250—अन्य सामाजिक सेवायें—800—अन्य व्यय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें—0101—अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजना (100% कें0स0) के मानक मद 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-31(P)/XXVII(3)/2012-13, दिनांक 26 जून,

2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय, (एमं**०एच०खान)** सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः— 👍 (1) / 07(66)/2008(TC-3) तद्दिनांकित। प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इल्ह्वानी-नैनीताल।

3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून!

4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।

वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, हरिद्वार, ।

6. पैयजल अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

7. वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

9. आदेश पंजिका।

(१२५०एस० विट्या) उप सचिव।